



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 वैशाख 1941 (श०)

(सं० पटना 593) पटना, बृहस्पतिवार, 2 मई 2019

सामान्य प्रशासन विभाग

तार्किक आदेश

24 अप्रैल 2019

सं० 08/न्या०-05-28/2014-5391/सा०प्र०—सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-5479/2015 सूर्यनारायण सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 29.01.2019 को पारित आदेश की प्रति प्राप्त हुआ है, जिसमें वादी से वसूल की गई राशि 1.25 लाख रुपया के संबंध में वादी द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग में समर्पित अभ्यावेदन दिनांक 28.10.2013 के संबंध में आठ सप्ताह के अन्दर सकारण आदेश पारित करने का आदेश है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश का मुख्य अंश निम्नवत है:—

‘This court would observe that the since the petitioner's application has been pending for more than five years the respondent no. 2 should dispose off the same by reasoned and speaking order in accordance with law expeditiously and preferably within a period of eight weeks from the date of receipt/production of a copy of this order. The petitioner's entitlement to refund of the amounts recovered shall be subject to decision of the respondent no. 2 on the representation dated 28.10.2013 submitted by the petitioner.’

उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में स्थिति निम्न प्रकार स्पष्ट की जा रही है:—

2. सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-6102/2006 रास बिहारी राम बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 17.05.2011 को पारित आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए मैजिस्ट्रीयल जाँच में विलम्ब करने वाले दोषी पदाधिकारी श्री सूर्य नारायण सिंह एवं श्री शालिग्राम साह (दोनों बि०प्र०से० के पदाधिकारी) से सरकार द्वारा भुगतान की गई मुआवजा की राशि 2,50,000/- वसूली करने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई का प्रस्ताव कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना के पत्रांक 1515 दिनांक 11.04.2012 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को प्राप्त हुआ।

3. सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-6102/2006 में पारित न्यायादेश एवं कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना से प्राप्त प्रस्ताव के अनुपालन में राशि की वसूली के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 7718 दिनांक 30.05.2012 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण पुछा गया। उक्त क्रम में स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु श्री सिंह द्वारा कतिपय अभिलेखों की मांग (पत्रांक 144 दिनांक 09.06.2012 द्वारा) किया गया। तत्पश्चात विभागीय पत्रांक 11684 दिनांक 22.08.2012 द्वारा यह निदेश दिया गया कि आपके द्वारा मांगी गयी अभिलेख/सूचना इस विभाग में उपलब्ध नहीं है, अतः संबंधित जिला पदाधिकारी, रोहतास से वांछित अभिलेख प्राप्त कर अपना स्पष्टीकरण शीघ्र उपलब्ध कराया जाय। पत्र की प्रतिलिपि जिला

पदाधिकारी, रोहतास को भी दी गयी। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में विभागीय पत्रांक 14912 दिनांक 31.10.2012 श्री सिंह को पुनः स्मारित किया गया। लम्बी अवधि तक स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने के कारण सम्यक् विचारोपरांत सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-6102/2006 में दिनांक 17.05.2011 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति जिला पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया को भेजते हुए श्री सिंह से 1,25,000/- रुपया वसूली करने का निदेश विभागीय पत्रांक 2198 दिनांक 07.02.2013 द्वारा दिया गया।

4. तत्पश्चात् श्री सिंह, बि०प्र०से० के पत्रांक 1532 दिनांक 28.10.2013 द्वारा स्पष्टीकरण का जबाब विभाग में प्राप्त हुआ। जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि जिला पदाधिकारी द्वारा उन्हें कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया न ही कोई जबाब दिया गया। इसी बीच सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा राशि कटौती का अनुरोध जिला पदाधिकारी प. चम्पारण (बेतिया) से किया गया। तत्पश्चात् उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सिविल रिव्यू नं०-160/2013 दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.08.2013 को पारित न्यायादेश में उन्हें अपना पक्ष Enquiry officer अथवा Disciplinary Authority के समक्ष रखने को कहा गया। जिसके अनुपालन में श्री सिंह द्वारा अपने उक्त स्पष्टीकरण (पत्रांक 1528 दिनांक 28.10.2013) में ही निम्न अनुरोध किया गया:-

“यथाशीघ्र दोषियों की पहचान के लिए कार्रवाई की जाय। इसके लिए कमिटी गठित की जाय अथवा विभागीय कार्यवाही चलाई जाय। हर हाल में दोषी पदाधिकारी को चिन्हित कर उनसे ही वसूली की कार्रवाई की जाय। पत्र में उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि वे कार्यपालक दंडाधिकारी, सासाराम के पद पर पदस्थापित थे। दिनांक 23.04.2003 को उन्हें Inquest एवं Enquiry के लिए आदेश दिया गया। वे दिनांक 23.04.2003 Inquest Report जमा कर दिये। जाँच भी प्रारम्भ की गयी थी, लेकिन शारीरिक तकलीफ (Urethral Stricture) के कारण Urine Discharge में काफी दिक्कत हो रही थी, जिसके कारण स्थानीय चिकित्सकों से ईलाज करा रहे थे। स्थिति ज्यादा खराब हो जाने अर्थात् पेशाब बन्द हो जाने के कारण हॉस्पिटलाईज होना पड़ा। फलस्वरूप दिनांक 16.05.2003 से 06.08.2003 तक कुल-83 दिनों तक मेडिकल ग्राउण्ड पर रुपांतरित अवकाश में रहे। परिणाम स्वरूप श्री शालिग्राम साह, बि०प्र०से० दूसरे पदाधिकारी को Enquiry Conduct करने का आदेश दिया गया। इस प्रकार शारीरिक कष्ट के कारण ससमय Enquiry Conduct नहीं हो सका एवं दूसरे पदाधिकारी को Enquiry करना पड़ा। उक्त तथ्यों के आलोक में दोषी पदाधिकारी को चिन्हित कर वांछित राशि वसूल करने एवं उन्हें वसूली से मुक्त करने का अनुरोध श्री सिंह द्वारा किया गया।”

5. श्री सिंह से प्राप्त उक्त स्पष्टीकरण (अभ्यावेदन) की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। सम्यक् विचारोपरांत विभागीय पत्रांक-18851 दिनांक 11.12.2013 द्वारा श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण (अभ्यावेदन) सहायक कारा महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को भेजते हुए राशि की वसूली हेतु संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध दायित्व निर्धारण के विन्दू पर स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में विभागीय पत्रांक-12930 दिनांक 16.04.2014 पत्रांक-12163 दिनांक 19.08.2015 एवं पत्रांक-17397 दिनांक 17.12.2015 द्वारा स्मारित भी किया गया। तत्पश्चात् प्रभारी पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4022 दिनांक 06.07.2016 द्वारा श्री सिंह के स्पष्टीकरण (अभ्यावेदन) पर अपना मंतव्य उपलब्ध कराया गया। प्राप्त मंतव्य निम्न प्रकार है :-

“मजिस्ट्रीयल जाँच प्रतिवेदन विलंब से समर्पित करने से संबंधित बचाव में श्री सिंह का कहना है कि उन्हें दिनांक 23.04.2003 को मृत्यु की घटना का Inquest एवं Enquiry प्रतिवेदन तैयार करने का निदेश दिया गया था। इसके अनुपालन में इनके द्वारा दिनांक 23.04.2003 को Inquest Report जमा किया गया, परन्तु दिनांक 16.05.2003 से 06.08.2003 तक कुल-83 दिनों तक मेडिकल ग्राउण्ड पर रुपांतरित अवकाश पर रहने की वजह से MER तैयार नहीं किया जा सका। फलस्वरूप जिला पदाधिकारी के पत्रांक-1617/गो०, दिनांक 02.06.2003 द्वारा श्री शालिग्राम साह को मजिस्ट्रीयल जाँच करने का आदेश दिया गया था। इन्होंने अपने स्पष्टीकरण के समर्थन में उपरोक्त वर्णित तथ्यों से संबंधित कोई भी कागजात साक्ष्य के रूप में संलग्न नहीं किया है। बल्कि समुचित रूप से बचाव पक्ष रखने हेतु उक्त घटना से संबंधित कागजातों यथा सी०डब्ल्यू०जे०सी०सं०- 6102/2006 का Complaint, IR, PMR तत्कालीन कारा चिकित्सक का नाम आदि की माँग किये।

अन्ततः कारा विभाग द्वारा यह मंतव्य दिया गया कि :- बचाव साक्ष्य स्पष्टीकरण में संलग्न नहीं है तथा मेडिकल आधार पर रुपांतरित अवकाश में जाने से पूर्व दिनांक 23.04.2003 से 16.05.2003 तक कुल-24 दिनों तक में भी MER जमा नहीं करने के कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः श्री सूर्य नारायण सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण असंतोषप्रद है।”

6. श्री सिंह का अभ्यावेदन/स्पष्टीकरण (दिनांक 28.10.2013) असंतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में न्यायादेश के अनुपालन में मुआवजा की राशि वसूली के लिए नियमानुसार विभागीय कार्यवाही संचालित करने के निमित्त विभागीय पत्रांक-11486 दिनांक 24.08.2016 द्वारा महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना से श्री सिंह के विरुद्ध आरोप, प्रपत्र ‘क’ (साक्ष्य सहित) उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। तदुपरांत संयुक्त सचिव-सह-निदेशक प्रशासन कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना के पत्रांक 5780 दिनांक 20.09.2016 द्वारा श्री सूर्य नारायण सिंह, बि०प्र०से० के विरुद्ध विहित प्रपत्र-“क” में आरोप पत्र गठित कर साक्ष्य सहित उपलब्ध कराते हुए विभागीय कार्यवाही सांस्थित करने का अनुरोध किया गया। इस बीच श्री सिंह दिनांक 30.09.2014 को सेवानिवृत्त हो गये।

7. श्री सिंह के विरुद्ध प्राप्त आरोप, प्रपत्र-“क” एवं साक्ष्य सहित सम्पूर्ण मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई। सम्यक् समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री सिंह दिनांक 30.09.2014 को सेवानिवृत्त हो गये हैं एवं घटना वर्ष 2003-04 की है। अतएव इनके विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43 बी0 के तहत विभागीय कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती है। फलतः बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 139 के तहत श्री सिंह के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप प्रपत्र-“क” के साथ विभागीय पत्रांक 9844 दिनांक 02.08.2017 द्वारा मुआवजा की राशि की वसूली के निमित्त बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 139 के तहत श्री सिंह से स्पष्टीकरण पूछा गया। पत्रांक 15875 दिनांक 13.12.2017 द्वारा स्पष्टीकरण हेतु स्मारित भी किया गया। श्री सिंह द्वारा अभ्यावेदन (दिनांक 19.12.2017) समर्पित करते हुए आरोप आरोप पत्र की प्रति की मांग की गई। जिसके क्रम में पुनः विभागीय पत्रांक 35 दिनांक 02.01.2018 द्वारा श्री सिंह को आरोप पत्र/साक्ष्य सहित भेजते हुए शीघ्र स्पष्टीकरण देने हेतु निदेशित किया गया। श्री सिंह द्वारा अभ्यावेदन (दिनांक 16.01.2018) समर्पित करते हुए स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु अतिरिक्त 15 दिनों की समय की मांग की गई। तत्पश्चात् श्री सिंह से स्पष्टीकरण (दिनांक 05.02.2018) प्राप्त हुआ।

8. अपने स्पष्टीकरण में श्री सिंह द्वारा उल्लेख किया गया है कि यह मामला काफी पुराना (वर्ष 2003 का) है एवं वे दिनांक 30.09.14 के अपराहन में अपर समाहर्ता, लखीसराय के पद से वार्धक्य सेवानिवृत्त हो गये। सेवानिवृत्ति के उपरान्त उन्हें पेंशन का 90 प्रतिशत/उपादान की राशि में से रु0 1,25,000/- छोड़कर, जो भी अनुमान्य है, भुगतान हुआ/हो रहा है। जिस मामले से संबंधित स्पष्टीकरण की मांग उनसे न्यायादेशों में उल्लिखित बातों के आधार पर की जा रही है वह पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। क्योंकि यह मामला उनके सेवाकाल में रहते हुये उत्पन्न हुआ तथा उसके बाद उनके द्वारा अपना पक्ष रखते हुये दो बार अलग-अलग माध्यमों से अभ्यावेदन (दिनांक 28.10.13 को स्वयं द्वारा एवं 04.11.13 को जिला पदाधिकारी के पत्रांक 1041 दिनांक 04.11.13 द्वारा) समर्पित किया गया, जिसपर विभागीय निर्णय लम्बित है। जिस मामले में उन्हें मजिस्ट्रेटियल जाँच हेतु प्रतिनियुक्त किया गया था, ड्यूटी पर रहते हुए उन्होंने इक्वेस्ट रिपोर्ट समर्पित कर दिया था। परन्तु बाद में बीमार हो जाने एवं शारीरिक असमर्थता के कारण उन्हें छुट्टी पर जाना पड़ा। उनकी आवेदित छुट्टी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्वीकृत हुयी। तत्पश्चात् उनके स्थान पर एक अन्य पदाधिकारी प्रतिनियुक्ति किये गये। इस आधार पर उन्होंने स्वयं के द्वारा किसी प्रकार का विलंब करने के आरोपों का प्रतिकार करते हुए आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया। स्पष्टीकरण के साथ श्री सिंह द्वारा पूर्व समर्पित अभ्यावेदन दिनांक 28.10.2013 की छाया प्रति भी संलग्न किया गया।

9. श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रपत्र-‘क’, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश सहित पूरे मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी एवं माननीय उच्च न्यायालय के निष्कर्ष के आधार पर यह पाया गया कि श्री सिंह का कार्य संतोषप्रद नहीं रहा और उन्होंने स्पष्ट जाँच प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया। **Inquest** रिपोर्ट में बयानों के आधार पर यद्यपि मृत्यु का कारण आत्महत्या बताया, तथापि अपना मंतव्य अंकित नहीं किया। श्री सिंह दिनांक 16.05.2003 से चिकित्सा अवकाश पर प्रस्थान कर गये और कुल 83 दिनों तक चिकित्सा के लिए रुपांतरित अवकाश पर रहे। दिनांक 23.04.2003 को उन्होंने **Inquest** रिपोर्ट हस्ताक्षरित किया था एवं दिनांक 16.05.2003 को वे चिकित्सा अवकाश में प्रस्थान किए। इस बीच करीब 22 दिनों का समय था, जिसमें वे जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर सकते थे, परन्तु उन्होंने जाँच प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया। संजीत कुमार बंदी ने आत्महत्या की, इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं श्री शालीग्राम साह के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है, लेकिन इसको माननीय उच्च न्यायालय ने पूर्णतः स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार श्री सिंह के विरुद्ध कर्तव्य एवं दायित्व के निर्वहन में लापरवाही का दोष प्रमाणित हुआ तथा उनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

10. अतएव उक्त वर्णित तथ्यों एवं सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-6102/2006 में दिनांक 17.05.2011 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7152 दिनांक 31.05.2018 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम-139 के संगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए 1,25,000/- रु0 (भुगतान की गई मुआवजा की राशि 2,50,000/- का आधा) की वसूली पेंशन/उपादान की राशि से करने का दंड श्री सिंह को संसूचित किया गया।

11. उक्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7152 दिनांक 31.05.2018 द्वारा संसूचित दंड के विरुद्ध श्री सिंह द्वारा पुनरीक्षण अभ्यावेदन (दिनांक 02.08.2018) समर्पित किया गया। श्री सिंह से प्राप्त पुनरीक्षण अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। सम्यक् समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री सिंह द्वारा पुनरीक्षण अभ्यावेदन में किसी नये तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। बल्कि पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण में उल्लिखित तथ्यों के सदृश्य ही पुनरीक्षण आवेदन में भी उल्लेख किया गया है। उनके द्वारा कोई ऐसा नया तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसपर अलग से विचार किया जा सके।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 13814 दिनांक 15.10.2018 द्वारा श्री सिंह से प्राप्त पुनरीक्षण अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में 2,50,000/- रु0 का आधा भाग यानि 1,25,000/- रु0 बिहार पेंशन नियमावली के नियम-139 के संगत प्रावधानों के तहत श्री सिंह के बकाया पेंशन/उपादान की राशि से कटौती करने संबंधी निरूपित दंड को पूर्ववत बरकरार रखा गया।

12. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-6102/2006 रास बिहार राम बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 17.05.2011 को पारित न्यायादेश के आलोक में मुआवजा राशि की वसूली हेतु श्री सिंह से पत्रांक 7718 दिनांक 30.05.2012 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री सिंह ने अपने पत्रांक 1532

दिनांक 28.10.2013 द्वारा स्पष्टीकरण का उत्तर समर्पित किया। उक्त स्पष्टीकरण (अभ्यावेदन दिनांक 28.10.2013) के साथ ही उनके द्वारा Civil Review No:-160/2013 में पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए उल्लेख किया गया कि उक्त वाद में पारित आदेश के क्रम में उन्हें अपना पक्ष Enquiry officer अथवा Disciplinary Authority के समक्ष रखना है। श्री सिंह से प्राप्त उक्त स्पष्टीकरण अथवा अभ्यावेदन (दिनांक 28.10.2013) की समीक्षा विभागीय स्तर पर करते हुए राशि वसूली संबंधी उत्तरदायित्व निर्धारण के बिन्दु पर सहायक कारा महानिरीक्षक से मंतव्य की मांग की गयी। कारा विभाग से प्राप्त मंतव्य में श्री सिंह के स्पष्टीकरण (अभ्यावेदन) दिनांक 28.10.2013 को असंतोषप्रद बताया गया। तत्पश्चात कारा विभाग से श्री सिंह के विरुद्ध आरोप, प्रपत्र-“क” प्राप्त हुआ। श्री सिंह के दिनांक 30.09.2014 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उनके विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया एवं विभागीय पत्रांक 9844 दिनांक 02.08.2017 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए श्री सिंह से स्पष्टीकरण पुछा गया। श्री सिंह से स्पष्टीकरण का उत्तर प्राप्त हुआ। जिसमें उनके द्वारा पुनः पूर्व के अभ्यावेदन/स्पष्टीकरण दिनांक 28.10.2013 की प्रति संलग्न किया गया। श्री सिंह के विरुद्ध गठित आरोप पत्र/उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध कराये गये अभिलेख के क्रम में पुरे मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी एवं आरोपों को प्रमाणित पाते हुए उन्हें 1,25,000/- रुपये वसूली का दंड संसूचित किया गया है। उक्त निर्गत दंडादेश के विरुद्ध श्री सिंह द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को भी विचारोपरांत अस्वीकृत किया गया है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि Civil Review No: 160/2013 में पारित आदेश एवं उक्त क्रम में श्री सिंह द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक 28.10.2013 का निष्पादन विभाग द्वारा पूर्व में ही विधिवत रूप से किया जा चुका है एवं श्री सिंह के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 139 के तहत कार्रवाई के पश्चात उनसे मुआवजा की राशि 1,25,000/- रुपये की वसूली का निर्णय लिया गया है।

13. वसूली के दंड के विरुद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में पुनः एक याचिका सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-...../2019 दायर किया गया है। जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

आदेश से,
आमिर सुबहानी,
अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 593-571+10 डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>